

SHRI N. JOTHI : Sir, this is a very serious issue.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: It may be very serious but without notice we don't accept it. ...*(Interruptions)*...

SHRI C. RAMACHANDRAIAH: Sir, it is very unfair. ...*(Interruptions)*... I was permitted by the Chair yesterday.

श्री राशिद अल्वी: सर, यूपी के एमएलएज़ मारे जा रहे हैं ...*(व्यवधान)*... एमएलएज़ के ऊपर डंडे पड़ रहे हैं ...*(व्यवधान)*...

SHRIMATI BRINDA KARAT (West Bengal): Sir,...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I am calling you. ...*(Interruptions)*... I am giving you the first chance. ...*(Interruptions)*... The House is adjourned for ten minutes.

The House then adjourned at nine minutes past twelve of the clock.

The House re-assembled at eighteen minutes past twelve of the clock,

[MR. DEPUTY CHAIRMAN in the Chair.]

Murder of dalits at Kherlanji in Maharashtra

श्रीमती वृंदा कारत (पश्चिमी बंगाल) : थैंक्यू सर, मैं खैरलांजी की एक घटना के बारे में आदरणीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। सब जानते हैं कि दो महीने पहले एक दलित भोतमांगे परिवार के चार सदस्यों की निर्मम हत्या की गई। हमारे पास ऐसे कोई शब्द भी नहीं हैं कि हम इसकी भर्त्सना कर सकें, लेकिन उसके पीछे जो पॉलिटिक्स है, वह मैं कुछ चार मुद्दे उठाना चाहती हूँ। पहला मुद्दा यह है कि यह घटना रोकी जा सकती थी और अगर नहीं रुकी तो उसके पीछे पूर्ण रूप से प्रशासन और पुलिस का दलित विरोधी रवैया रहा है। शुरू से अंत तक, जब पहले घटना हुई, उस घटना के दो हफ्ते तक पुलिस ने एफआईआर भी कतई दर्ज नहीं की और जब एफआईआर दर्ज की तो एससी एक्ट के तहत जो धारा लगनी चाहिए वह भी नहीं लगाई। और पुलिस ने उन अपराधियों की जमानत तक करवाने के लिए भी पहलकदमी की। निश्चित रूप से जब प्रशासन का ऐसा रवैया होगा तो अपराधियों का हौसला बुलन्द होगा और जिस दिन उनको जमानत मिली उसी दिन जाकर उन्होंने भोतमांगे परिवार पर हमला किया। इसलिए किया कि वे आत्मनिर्भर थे तथा वे गांव में किसी प्रभावशाली जाति के सामने झोली फैलाकर भीख नहीं मांग रहे थे। उन्होंने यह भी कहा कि हमारे बराबर के अधिकार हैं तो ऐसा उनको बर्दास्त नहीं हुआ और जो क्रूरता है सर, वह क्रूरता क्या थी, जब मैं वहां गांव में गई तो उन्होंने अपनी बच्ची का फोटो दिखाया। सर, उस 18 साल की बच्ची प्रियंका के शरीर का एक इंच भी हिस्सा बचा हुआ

नहीं था, जिस पर अत्याचार के निशान नहीं थे। लेकिन जब मैंने पोस्ट-मार्टम रिपोर्ट देखी, उस पोस्ट-मार्टम रिपोर्ट में किसी भी प्रकार के घाव का कोई जिक्र नहीं था। यहां तक कि एक 18 साल की लड़की और उसकी 43 साल की मां सुरेखा को वस्त्रहीन करके पूरे गांव में घुमाया, लेकिन आप डाक्टरों की और प्रशासन की मिलीभगत देखिए, उन्होंने एक vaginal swab भी नहीं किया, जो अनिवार्य होता है। इसलिए रेप साबित नहीं हुआ, जबकि पूरा गांव जानता है कि उन औरतों के साथ रेप भी हुआ।

सर, दूसरी बात यहां तक भी आ गई है कि जब सरकार ने कोई सही कार्यवाही नहीं की और उन्होंने पूरे कांड को छिपाने का काम किया, उसके बाद जब दलित खुद सड़कों पर उतरे, तो महाराष्ट्र सरकार का क्या रवैया था? आर. आर. पाटिल साहब ने यह घोषणा कर दी कि जो सड़कों पर पहुंचे हैं, ये सब नक्सलाइट हैं। इसका मतलब यह है कि अगर हम किसी अपराध के खिलाफ, इस तरह के अत्याचार के खिलाफ, सड़कों पर उतरें, तो हम नक्सलवादी हो गए। यह क्या है? जब हम वहां गए और पता चला कि बहुत सारे दलित एक्टिविस्ट को गिरफ्तार कर लिया है, 307 में गिरफ्तार कर लिया है, तो मैंने खुद वहां जो Special आई.जी. हैं, उनसे बात की। हमने उनसे पूछा कि आप इनको क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि इन्होंने बगैर सबूत के आरोप लगाया है कि बलात्कार भी हुआ, इसलिए हमने इनको गिरफ्तार किया है। मतलब एक तो उन्होंने अपराध को छिपाने की कोशिश की और जब वहां के लोगों ने इसका विरोध किया तो उल्टे उनको गिरफ्तार कर लिया। वे आज भी जेल में बंद हैं। उनको तुरंत रिहा किया जाए।

सर, जब हम प्रधान मंत्री जी से मिले, तो प्रधान मंत्री जी ने सहानुभूति दिखाई और कहा कि वह खुद मुख्य मंत्री जी से बात करके इसमें हस्तक्षेप करेंगे। लेकिन आज भी मेरे पास नागपुर से टेलिफोन आया, आज भी सैकड़ों की तादाद में उनकी गिरफ्तारी चल रही है। उनकी नहीं जिन्होंने इसका पूरा साथ दिया, उनकी गिरफ्तारी चल रही है, दलितों की गिरफ्तारी चल रही है, जिन्होंने इसका विरोध किया।

सर, इसीलिए हमारी चार मांगें हैं - इस मामले की सीबीआई जांच तो हो ही रही है, लेकिन वह टाइम बाउंड हो। दूसरी बात, सजा प्रशासन में किसको मिली है, केवल एक कांस्टेबल और एक लोअर रैंकिंग पुलिस पर्सनल को और इसीलिए हमने कहा कि जो सीनियर पुलिस आफिशियल्स इसमें शामिल हैं, जो वहां के डाक्टर्स इसमें शामिल हैं, उनके ऊपर क्रिमिनल प्रोसीजर का केस लगाकर, उनको तुरन्त जेल में भेजा जाए, तभी एक सही मैसेज उन तक जाएगा।

सर, तीसरी बात अनिवार्य है कि जो वहां पूरा एक माहौल है, पूरे देशभर में आज दलितों के ऊपर जो अत्याचार बढ़ रहे हैं, उनको रोकने के लिए हम आपके माध्यम से प्रधान मंत्री जी को यह सुझाव देना चाहते हैं कि तुरंत तमाम प्रदेशों की, जहां इस प्रकार की

घटनाएं घटती हैं, अभी पता चला कि मध्य प्रदेश में एक औरत के साथ इसी प्रकार की एक घटना घटित हुई, उसको वस्त्रहीन करके उसके साथ बलात्कार किया गया, ऐसे मामले पहले भी हुए हैं, इसलिए यह जो जातिगत घृणा और नफरत दलितों के खिलाफ फैल रही है, इसके ऊपर सख्त कार्यवाही हो, इसके लिए हम चाहते हैं कि प्रधान मंत्री जी तमाम गृह मंत्रियों की मीटिंग बुलाकर एक मिशन मोड में, एक प्लान बनाएं कि किस प्रकार उन प्रशासनकर्ताओं के खिलाफ कार्यवाही होगी, जो कांस्टीबल्युशन मंडेट को डिफेंड नहीं करते हैं। सर, आज भी जितने इस प्रकार के दलित कांड हैं, चाहे दुलैना का कांड हो, आज तक किसी अपराधी को सजा नहीं दी गई है। इस प्रकार के जितने भी कांड हैं, उन्हें फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में भेजा जाना चाहिए।

सर, आखिर में, मैं यह कहना चाहती हूँ कि हम लोग किसी न किसी राजनीतिक दल से सम्बद्ध रखते हैं। हम लोगों में से बहुत सारे लोग हैं, जो उनकी नुमाइंदगी भी करते हैं, जहां इस प्रकार की जातीय घृणा का एक माहौल है। सर, मुझे सबसे ज्यादा खेद इस बात का है कि वहां जो चुने हुए नुमाइंदे हैं, वे सब महाराष्ट्र में विपक्षी दल के हैं, एमएलए भी है और एमपी भी हैं। वे दोनों विपक्षी दल के हैं। सर, उन्होंने क्या किया, क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि कारण क्या है, उस गांव में केवल तीन दलित परिवार हैं, तो हो सकता है कि उन्होंने सोचा कि उसके वोट की कोई कीमत ही नहीं है या क्या कारण था कि वह बिल्कुल खामोश रहे।...(व्यवधान)...

श्री एस. एस. अहलुवालिया (झारखंड) : यह आप गलत बोल रही हैं।

श्रीमती वृंदा कारत : आप बता दें...(व्यवधान)...जो मैंने खुद देखा है और जो दलितों ने कहा...(व्यवधान)... मैंने पार्टी का नाम नहीं लिया। मैं पॉलिटिक्स की बात कर रही हूँ।...(व्यवधान)...

श्री एस. एस. अहलुवालिया : उन्होंने एजीटेशन को लीड किया।

श्रीमती वृंदा कारत : ऐसी भयानक घटना में अगर वहां की तमाम पॉलिटिकल पार्टियां खड़ी होकर दलित परिवार का साथ नहीं देंगी, तो जितने भी परमाणु हथियार बनाकर हम महाशक्ति बनने की कोशिश कर लें, हिन्दुस्तान महान नहीं होने वाला है - यही मैं कहना चाहती हूँ।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You just associate yourself with it.

श्रीमती सुषमा स्वराज (मध्य प्रदेश) : उपसभापति जी, मैं अपनी समूची पार्टी की ओर से इस विषय से संबद्ध करती हूँ। जो विषय यहां उठाया गया है, यह विषय केवल महिलाओं के उत्पीड़न का नहीं बल्कि दलितों के प्रति अपराध का भी है।...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : एक मिनट रुकिए। ...(व्यवधान)...

SHRI PRAVEEN RASHTRAPAL (Gujarat): Sir, I have visited in the Enquiry Committee. ...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Then, you should not ...(Interruptions)...

श्रीमती सुषमा स्वराज : इस तरह के अपराध करने वाले अपराधियों को ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : आप बैठिए, पहले उनको बोलने तो दो। ...(व्यवधान)...

श्रीमती सुषमा स्वराज : इस तरह की घटना करने वाले अपराधियों को यदि सरकार का संरक्षण मिलता है, तो अपराध का प्रभाव दोगुना हो जाता है। जो मांगें वृंदा जी ने रखी हैं, उसमें एक मांग मैं और जोड़ना चाहती हूँ कि जो वहां पर एजीटेशन किया गया, उस एजीटेशन के बाद लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वह एजीटेशन लोगों को न्याय दिलाने के लिए था, इसलिए उस आंदोलन में जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं, उनको भी तुरंत छोड़ा जाए और इन अपराधियों को कठोर से कठोर दंड दिया जाए, यह हमारी मांग है।...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : श्री पचौरी ...(व्यवधान).... नहीं, आपकी पार्टी से बोल चुकी हैं।...(व्यवधान)...

श्री मंगनी लाल मंडल (बिहार): सभापति महोदय, मैं इसका समर्थन करता हूँ। उनको मैं बधाई देता हूँ। ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : केवल समर्थन कीजिए। ...(व्यवधान)...

SHRI R. SHUNMUGASUNDARAM (Tamil Nadu): Sir, I also associate myself with this issue. ...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The entire House associates itself with this. ...(Interruptions)...

श्री मंगनी लाल मंडल (बिहार): इस दृष्टिकोण से नहीं देखा जाता है। यह दलित उत्पीड़न और सामाजिक उत्पीड़न का मामला है, इसलिए मैं यह मांग रखता हूँ कि...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : मंडल जी, बस ठीक है। ...(व्यवधान).... श्री सुरेश पचौरी। ...(व्यवधान)...

श्री शाहिद सिद्दिकी (उत्तर प्रदेश): सरकार का टोटल फेल्योर है।...(व्यवधान)...

﴿شری شاہد صدیقی : سرکار کا ٹوٹل فیلپور ہے مداخلت﴾

श्री नारायण सिंह केसरी (मध्य प्रदेश): उपसभापति महोदय...(व्यवधान)...

श्री अबू आसिम आजमी (उत्तर प्रदेश): महाराष्ट्र में लोकतंत्र खत्म हो गया है।...(व्यवधान)...

† [شری ابو عاصم اعظمی: مہاراشٹر میں لوک تانترا ختم ہو گیا ہے مداخلت۔]

SHRI SHAHID SIDDIQUI: So far as minorities and Dalits are concerned, they are being oppressed in Maharashtra. ...(Interruptions)...

SHRI B.K. HARIPRASAD (Karnataka): Mr. Deputy Chairman, Sir, similar incidents have happened in Karnataka also where the Dalits...
...(Interruptions)... ...they have been boycotted in the society.
...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That is why she has suggested that there should be a meeting, in this regard. ...(Interruptions)... Now, let the hon. Minister respond to it. ...(Interruptions)...

SHRI C. RAMACHANDRAIAH (Andhra Pradesh): With great concern, the entire House is associating itself with it. ...(Interruptions)...

श्री नारायण सिंह केसरी : महोदय ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : बस हो गया। आपकी पार्टी से वे बोल चुकी हैं।...(व्यवधान)... पूरी बात हो गयी है। ...(व्यवधान)...

श्री नारायण सिंह केसरी: हमारी भी बात सुनी जाए। ...(व्यवधान)... इस देश में...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : आपकी लीडर ने असोसिएट किया है। आप बैठिए।...(व्यवधान)...

श्री वीरेन्द्र भाटिया (उत्तर प्रदेश) : महोदय, हमारी पार्टी को भी मौका मिलना चाहिए।
...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : शाहिद सिद्दिकी साहब बोल चुके हैं।...(व्यवधान)...

श्री शाहिद सिद्दिकी : सर, बोला नहीं था। ...(व्यवधान)...

† [شری شاہد صدیقی: سر، بولا نہیں تھا مداخلت۔]

श्री वीरेन्द्र भाटिया : सर, हमें बोलने दीजिए। ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : आप लोग केवल असोसिएट कीजिए। इसमें कोई डिबेट नहीं है। उनके सेंटीमेंट्स को उन्होंने एक्सप्रेस किया, आप उसको असोसिएट कीजिए। आपकी पार्टी से असोसिएट कर चुके हैं।

श्री वीरेन्द्र भाटिया : सेंटीमेंट्स तो हमारे हैं ही। हम इनके साथ ज्वाइन करते हैं लेकिन ये घटनाएं महाराष्ट्र में ही क्यों हो रही हैं? महाराष्ट्र में ही. ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : वह सवाल बाद में कहिए। ...(व्यवधान)... उन्होंने सिर्फ महाराष्ट्र में ही नहीं, दूसरी स्टेट्स में भी कहा है। ...(व्यवधान)... आप बैठिए। ...(व्यवधान)...

श्री वीरेन्द्र भाटिया : महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था समाप्त हो चुकी है। इस पर विचार होना चाहिए। ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : आप बैठिए।...(व्यवधान)...

श्री नारायण सिंह केसरी : महोदय, इस देश में...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : आप बैठिए। ...(व्यवधान)... आप तीन आदमी इकट्ठे खड़े होकर बोल रहे हैं।...(व्यवधान)... कुछ रिकॉर्ड में नहीं जाएगा।...(व्यवधान)... पचौरी जी, आप बोलिए।

श्री अबू आसिम आजमी : *

श्री विनय कटियार (उत्तर प्रदेश) : *

श्री उपसभापति : मालेगांव बाद में आएगा। ...(व्यवधान)... आप बैठिए। अब मालेगांव को मत जोड़िए।...(व्यवधान)... कटियार जी, आप बैठिए। रिकॉर्ड में कुछ नहीं जाएगा। ...(व्यवधान)... कुछ रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। ...(व्यवधान)... पचौरी जी, आप बोलिए।

SHRIMATI BRINDA KARAT: Sir, Let us not dilute the Dalit issue. ...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no; I am not allowing it. ...(Interruptions)... Yes, Mr. Pachouri.

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी) : माननीय उपसभापति महोदय, आदरणीय सदस्या ने खेरलांजी, महाराष्ट्र में दलित परिवार पर जो जुल्म-ओ-सितम हुआ है, उसका जिक्र किया है। वह न केवल निन्दनीय है बल्कि अगर मैं यह कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि दलितों पर

जुल्म-ओ-सितम की जहां पर भी घटनाएं हो रही हैं, उनकी जितनी भर्त्सना की जाए, वह कम है। जहां तक इस घटना का प्रश्न है, मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि 14 नवम्बर को प्रिंसिपल सेक्रेटरी, महाराष्ट्र ने इस प्रकरण की सीबीआई जांच कराने के लिए पत्र प्रेषित किया था और 22 नवम्बर को सीबीआई ने इसकी जांच ...*(व्यवधान)*...

श्री उपसभापति : आप खामोश रहिए। ...*(व्यवधान)*... यह ठीक नहीं है।

श्री सुरेश पद्मौरी : जो लेटर मिला, उससे सहमति प्रदान करते हुए सरकार को अपना मन्तव्य भेजा। मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि 25 नवंबर को इस पूरे प्रकरण के सारे पहलुओं पर, मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि सारे पहलुओं पर जांच करने संबंधी 25 नवंबर को सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। मैं यह और कहना चाहता हूं कि इस पूरे प्रकरण की निष्पक्षता से और सारे पहलुओं से सी.बी.आई. जांच करेगी और हम कोशिश करेंगे कि जो भी इसमें दोषी पाए जाएं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिल सके।

Printing of skull bones and dead body on packets of Bidi

SHRI C. RAMACHANDRAIAH (Andhra Pradesh): Sir, thank you for permitting me to raise an important issue. On 5th July, 2006, the Health Ministry of Government of India issued a notification by which every *bidi* manufacturer has to print skull bones and dead body on every packet of *bidi*. We fully support the National Health Policy, as everybody in the House supports. But the only thing is, by virtue of educating the people we should desist them from smoking. But, instead of getting educated, people are being terrorised by these advertisements. Sir, all political parties in Andhra Pradesh have agitated on this and they made representations. I do not want to politicise the issue but I would like to draw the attention of the Government and get the problem solved.

All the political parties have made representations to the Health Minister. But the Health Minister was rather reluctant to change it. Andhra Pradesh is a very big tobacco growing State. Lakhs of farmers are producing tobacco. Secondly, it is one of the biggest bidi manufacturing States in the country. Around 3.5 crore bidi workers are dependent on this for their livelihood and in Andhra Pradesh, I was told that the figure is 1.5 million. And all are poor people. Girijans are collecting *tendu* leaves from the forest for the manufacture of these bidis. It is a cottage industry and in their respective homes they can roll the bidis. This is the convenience the workers have got. They can make their living by earning Rs.60-70 by rolling a thousand